

9,331 करोड़ रुपये के निवेश से लगेंगे 56 डिस्टिलरी प्लांट

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश परियोजनाओं की रखी जाएगी आधारशिला

जीबीसी

आनंद मिश्र • लखनऊ

11,615 लोगों को मिलेगा रोजगार

58 हजार से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की भी उम्मीद

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस-23) में हुए निवेश करारों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के जरिये जमीन पर उतारने के प्रयास अब मूर्त रूप लेते दिख रहे हैं। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करीब 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों (एमओयू) की आधारशिला रखेंगे। इस कड़ी में आबकारी विभाग ने भी जीआइएस में हासिल करीब एक तिहाई निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी की है। जीबीसी में डिस्टिलरी (आसवनी) सेक्टर की 9331 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखा जाना तय हो गया है।

आबकारी आयुक्त सैथिल पांडियन सी ने बताया कि जीबीसी के लिए फिलहाल 56 डिस्टिलरी इकाइयों का चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है। इनमें 35 इकाइयों ने जीआइएस के दौरान प्रदेश सरकार

प्रमुख इकाइयां जिनकी रखी जाएगी आधारशिला

कंपनी	निवेश राशि (करोड़ रुपये में)	प्रस्तावित स्थल
बिंदल पेपर लिमिटेड	660.00	बिजनौर
डब्ल्यूआइ वेंचर	600.00	बिजनौर
मां शीतला	528.00	मुरादाबाद
त्रिवेणी इंजीनियरिंग	300.00	बुलंदशहर
त्रिवेणी इंजीनियरिंग	300.00	मुरादाबाद
ग्लोबल स्पिट	200.00	लखीमपुर
वाईटीटी ग्रुप	250.00	शाहजहांपुर
आल्को बुल	160.00	मुजफ्फरनगर

से एमओयू किया था। वहीं, 21 ऐसी इकाइयों के भी भूमि पूजन की तैयारी है, जिनका एमओयू जीआइएस के दौरान नहीं हुआ था। आबकारी आयुक्त के अनुसार इन इकाइयों के धरातल पर उतरने से 11,615 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 58 हजार से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार का आकलन किया गया है। गत वर्ष जीआइएस में डिस्टिलरी सेक्टर के लिए 92 कंपनियों ने 33

हजार करोड़ रुपये के एमओयू प्रदेश सरकार से किए थे। इस क्षेत्र विशेष के माध्यम से जीबीसी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का लक्ष्य तय किया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद जीबीसी लक्ष्य संशोधित होने के बाद इसे बढ़कर 12,500 करोड़ रुपये किया गया था। इस लिहाज से लक्ष्य के सापेक्ष आबकारी विभाग का प्रदर्शन बेहतर आंका जा रहा है।